भ्रष्टाचार टेक्निकल इंस्पेक्टर की काली सल्तनत, कोयले के खेल में सरेआम डकैती!

भ्रष्टाचार की 'ब्लैक डायमंड' मंडी बनी बंगवार खदान

प्रदीप शर्मा

नवभारत, धनपुरी। सोहागपुर एरिया की बंगवार भूमिगत खदान इन दिनों कोयले के उत्पादन के लिए नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार के 'ओपन सेल' के लिए चर्चा में है। धनपुरी नगर के अंतिम छोर पर स्थित होने का फायदा उठाकर यहाँ के टेक्निकल इंस्पेक्टर मुकेश तिवारी ने खदान को अपनी जागीर बना लिया है। चर्चा है कि साहब की 'चांदी' इतनी कट रही है कि नियम-कानून का मज़ाक बना चुके हैं और भ्रष्टाचार की कालिख से डियो होल्डर्स (उपभोक्ता) का दम घुट रहा है।

वसूली का 'तिवारी मॉडल' हजार नहीं, लाखों का वारा-न्यारा

सूत्रों की मानें तो बंगवार खदान में लूट का एक सुव्यवस्थित तंत्र चल रहा है। टेक्निकल इंस्पेक्टर मुकेश तिवारी पर आरोप है कि वे रोड सेल के नाम पर अवैध वसूली का खुला खेल खेल रहे हैं। यहाँ प्रति गाड़ी ?1000 की 'गुंडा टैक्स' जैसी वसूली टैरेक्स लोडिंग और अन्य तथाकथित 'कालरी खर्च' के नाम पर डियो होल्डर्स से वसूली जा रही है। हैरानी की बात यह है कि बैंकर होने के बावजूद उपभोक्ताओं पर टैरेक्स लोडिंग के लिए अनैतिक दबाव बनाया जाता है। यदि आपको 'क्वालिटी कोयला' चाहिए, तो तिवारी जी का रेट फिक्स है— 50 प्रति टन! यानी एक गाड़ी लोड कराने के लिए उपभोक्ता को 5 से 8 हजार रुपये की अतिरिक्त चपत लगनी तय है। जो व्यापारी इस 'हफ्ता वसूली' के आगे नहीं झुकता, उसका डीओ जानबूझकर लैप्स करा दिया जाता है, जिससे कारोबारियों को लाखों का आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है।

भ्रष्टाचार की इस बहती गंगा में और कौन-कौन?

मुकेश तिवारी की इस 'बल्ले-बल्ले' वाली कार्यशैली के पीछे अकेले उनका हाथ नहीं है। खदान के गलियारों में चर्चा है कि भ्रष्टाचार की इस काली कमाई में ऊपर से नीचे तक एक सिस्टम शामिल है। अधिकारी, नोडल और कुछ चुनिंदा कर्मचारी इस बंदरबांट के बराबर के हिस्सेदार हैं। यही कारण है कि शिकायतों के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसा लगता है कि खदान में प्रबंधन का नहीं, बल्कि 'वसूली गैंग' का सिक्का चलता है।

सुविधाएं 'शून्य', लेकिन वसूली 'फुल'

एक तरफ जहां गर्मी के मौसम में टेक्निकल इंस्पेक्टर की 'पैसों की भूख' बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी ओर खदान परिसर में बुनियादी सुविधाओं का अकाल है। डियो होल्डर्स और ट्रक चालकों ने नाम न छापने की शर्त पर अपना दर्द बयां करते हुए कहा— 'यहाँ न पीने का साफ पानी है, न शौचालय की व्यवस्था। सुविधाओं के नाम पर सिर्फ धूल और धुआं मिलता है, लेकिन वसूली में एक रुपये की भी रियायत नहीं दी जाती।

महाप्रबंधक कब लेंगे संज्ञान

कोयला उपभोक्ताओं में अब आक्रोश फूट पड़ा है। व्यापारियों ने मुख्य महाप्रबंधक (जरूर) से गुहार लगाई है कि इस अवैध उगाही के खेल को तुरंत बंद किया जाए। क्या प्रबंधन इस 'काली कमाई' के सिंडिकेट को तोड़ने की हिम्मत दिखाएगा? या फिर मुकेश तिवारी जैसे रसूखदार कर्मचारियों को भ्रष्टाचार करने की खुली छूट मिलती रहेगी?

निष्पक्ष जांच की माँग

मुकेश तिवारी और उनके संरक्षकों के विरुद्ध निष्पक्ष जांच हो, संपत्ति का ब्यौरा खंगाला जाए और इस अवैध वसूली से उपभोक्ताओं को मुक्ति मिले। अन्यथा, यह असंतोष जल्द ही बड़े आंदोलन का रूप ले सकता है। 'कोयले के खेल में मुकेश तिवारी का 'भ्रष्टाचार मॉडल': पैसे दो तो कोयला मिलेगा, वरना डीओ लेप्स! आखिर कब तक चलेगा भ्रष्टाचार का यह खेल अब सबकी नजर महाप्रबंधक की ओर है। इस संबंध में उप क्षेत्रीय प्रबंधक से दूरभाष पर चर्चा करने की कोशिश की गई लेकिन उनके द्वारा फोन रिसीव नहीं किया गया।

संजय कुमार सिंह
उप क्षेत्रीय प्रबंधक बंगवार दामिनी

भीषण गर्मी में प्यास से जूझता धनपुरी, सार्वजनिक प्याऊ खोलने की उठी मांग

नवभारत, धनपुरी। भीषण गर्मी की मार झेल रहे धनपुरी नगर में इस वर्ष एक भी सार्वजनिक प्याऊ न खुल पाने से आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रविवार को साप्ताहिक बाजार के दौरान यह समस्या और भी विकराल रूप में सामने आई, जब दूर-दराज के गांवों से आए लोग और स्थानीय नागरिक पानी की तलाश में इधर-उधर भटकते नजर आए। बढ़ते तापमान ने हालात ऐसे बना दिए हैं कि जनजीवन अस्त-व्यस्त होता दिखाई दे रहा है। भीषण गर्मी में साप्ताहिक बाजार, जहां बड़ी संख्या में लोग अपनी दैनिक जरूरतों की पूर्ति के लिए जुटते हैं, वहां पीने के पानी की कोई समुचित व्यवस्था न होना चिंताजनक स्थिति को दर्शाता है। सब्जी व्यापारी, ग्राहक और राहगीर तपती धूप में प्यास से बेहाल दिखाई दिए। कई स्थानों पर लोग पानी की तलाश में दुकानों और घरों के दरवाजे खटखटाते नजर आए। हालांकि, कुछ संवेदनशील स्थानीय नागरिकों ने अपने स्तर पर घरों से ठंडा पानी उपलब्ध कराकर मानवीयता का परिचय दिया, लेकिन यह व्यवस्था सीमित और अस्थायी ही साबित हुई। इतनी बड़ी आबादी और भीड़ के लिए यह पर्याप्त नहीं है। ऐसे समय में नगर पालिका द्वारा सार्वजनिक प्याऊ की व्यवस्था न होना गंभीर लापरवाही के रूप में देखा जा रहा है। गौरतलब है कि पूर्व वर्षों में नगर के प्रमुख स्थानों—बाजार, बस स्टैंड और चौराहों पर अस्थायी प्याऊ खोलकर राहगीरों को राहत पहुंचाई जाती रही है। लेकिन इस बार अब तक ऐसी कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही, जिससे लोगों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। आमजन का कहना है कि भीषण गर्मी में पानी जैसी बुनियादी जरूरत की अनदेखी करना प्रशासन की जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने जैसा है।स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों ने नगर पालिका प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।

जल गंगा संवर्धन से अछूती नगर की एक मात्र नदी मुड़ना

▶ जीवनदायिनी नदी बनी शहर का नाला

सुनील मिश्रा

नवभारत, शहडोल। एक ओर प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान के नाम पर जल संरक्षण, जल स्त्रोतों और नदियों के पुनर्जीवन की बातें जोर-शोर से की जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर शहर की एकमात्र जीवनदायिनी मुड़ना नदी बदहाली की ऐसी तस्वीर पेश कर रही है, जो इन दावों पर सीधा सवाल खड़ा करती है। लगभग 40-50 किलोमीटर लंबी यह नदी, जो कभी स्वच्छ जल से लोगों की प्यास बुझाती और आस्था का केन्द्र हुआ करती थी, आज शहर का गंदा नाला बनकर रह गई है।

शहर में प्रवेश करती ही हो जाती है दूषित मैकल पर्वत से निकलकर केलमनियां होते हुए सोन नदी में मिलने वाली मुड़ना, शहर के करीब 5 किलोमीटर हिस्से में सबसे ज्यादा प्रदूषण झेल रही है। नगरीय प्रशासन ने शहर के अधिकांश नालों का रुख इसी नदी की ओर मोड़ दिया है। नतीजा यह है कि नदी में गिरने वाला गंदा पानी इसकी पहचान ही खत्म कर चुका है। हालात इतने बदतर हैं कि कभी जिस पानी में लोग स्नान करते थे, आज उसी के पास खड़ा होना भी मुश्किल हो गया है। विडंबना यह है कि जल गंगा संवर्धन जैसे अभियान के तहत तालाबों, कुओं और छोटे जलस्त्रोतों पर दिखावटी गतिविधियां तो हो रही हैं, लेकिन शहर की इस प्रमुख नदी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। अगर इसी अभियान में मुड़ना नदी को केंद्र में रखकर सफाई, अतिक्रमण हटाने और जल शुद्धिकरण का ठोस कार्य किया जाता, तो आज इसकी तस्वीर बदल सकती थी।

भारी अतिक्रमण का दंश झेल रही मुड़ना

नदी के किनारों पर सैकड़ों अतिक्रमण हो चुके हैं। लोगों ने पक्के निर्माण कर गंदे पानी का सीधा बहाव नदी में छोड़ दिया है। नगरपालिका इन अतिक्रमणों और प्रदूषण पर आंखें मूंदे बैठी है। न तो कोई ठोस कार्ययोजना दिखाई देती है और न ही अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई हुई है। पर्यावरण विशेषज्ञों की मानें तो शहर का गंदा पानी लगातार गिरने से नदी में घुलित ऑक्सीजन का स्तर बेहद कम हो चुका है, जिससे जलीय जीवों का अस्तित्व संकट में है। सेटलिंग टैंक और ऑक्सीकरण टैंक जैसे उपायों से इसे सुधारा जा सकता है, लेकिन इन सुझावों पर भी अमल नहीं हो रहा।सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब जल गंगा संवर्धन का उद्देश्य जल स्त्रोतों का संरक्षण और पुनर्जीवन है, तो फिर मुड़ना जैसी प्रमुख नदी इस अभियान से बाहर क्यों है। क्या अभियान केवल कागजों और फोटो तक सीमित है। अगर शासन-प्रशासन और आमजन मिलकर ईमानदारी से प्रयास करें, तो मुड़ना नदी को पुनर्जीवित करना असंभव नहीं है। लेकिन मौजूदा हालात देखकर यही लगता है कि जिम्मेदारों ने इस नदी को नाले के रूप में स्वीकार कर लिया है कृ और यही सबसे बड़ी विफलता है।

कानपुर बूचड़खाने ले जा रहे 2 ट्रकों से 30 मवेशी जब्त

▶ मवेशियों का क्रूरता पूर्वक ठूंसकर किया जा रहा था परिवहन

नवभारत,शहडोल। जिले के थाना सीधी पुलिस ने अवैध पशु परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो ट्रकों को पकड़कर 30 मवेशियों को मुक्त कराया है। यह कार्रवाई 28 अप्रैल 2026 को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर की गई। पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम कुदरी, अमझोर की ओर से दो डीसीएम ट्रक मवेशियों को अवैध रूप से लोड कर ब्यौहारी होते हुए उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित बूचड़खानों की ओर ले जाए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने ओदारी नदी के पास नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दौरान संदिग्ध दो ट्रक दिखाई दिए, जो पुलिस को देखकर भागने लगे, लेकिन घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया गया। जांच में सामने आया कि दोनों ट्रकों में मवेशियों को अमानवीय तरीके से ठूंस-ठूंसकर भरा गया था। उन्हें रस्सियों से कसकर बांधा गया था और न तो हवा की व्यवस्था थी, न ही पानी की।

पुलिस ने दोनों ट्रकों से कुल 30 मवेशी (25 पड़वा और 5 भैंस) बरामद किए, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 15 लाख रुपये बताई जा रही है। सभी मवेशियों को मुक्त कर सुरक्षित रूप से गौशाला सीधी में भेज दिया गया है।इस मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को चिन्हित किया हैकृअली असगर (निवासी इलाहाबाद), मोबिन खान (निवासी शहडोल), सनी साकेत (निवासी सतना) और सौरभ जायसवाल (निवासी सतना)। सभी के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, मप्र कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम और मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध पशु तस्करी में लगे गिरोहों में हड़कंप मच गया है।

छोटों पर कार्यवाही कर पीठ थपथापा रहा प्रशासन

▶ चंगेरा में अवैध कोयला खनन पर बड़ी कार्यवाही, दो खदानें सील, कोयला जब्त

नवभारत, बुढ़ार (शहडोल)। जिले में अवैध खनन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रशासन ने एक बार फिर बड़ी कार्यवाही करते हुए ग्राम चंगेरा में संचालित अवैध कोयला खनन पर सख्ती दिखाई।

मंगलवार को खनिज विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर दो अवैध रूप से संचालित पुरानी खदानों को बंद करा दिया और बड़ी मात्रा में कोयला जब्त किया। स्थानीय स्तर पर लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर टीम ने जब मौके का निरीक्षण किया, तो पाया कि बंद की जा चुकी खदानों को दोबारा सक्रिय कर अवैध खनन किया जा रहा था। अधिकारियों ने तत्काल कार्यवाही करते हुए जेसीबी मशीन की मदद से दोनों खदानों को पूरी तरह सील कर दिया, ताकि दोबारा खनन न हो सके। कार्यवाही के दौरान लगभग एक ट्रैक्टर-ट्रॉली कोयला जब्त किया गया, जिसे थाना बुढ़ार की अभिरक्षा में रखा गया है। मौके पर मौजूद शिकायतकर्ता ने बताया कि गांव के कुछ लोग बोरियों के माध्यम से कोयला निकालकर आसपास के ईंट भट्टों में बेच रहे थे, जिससे अवैध कारोबार लंबे समय से जारी था। संयुक्त टीम ने क्षेत्र में मौजूद अन्य छोटे-छोटे गड्ढों और खनन स्थलों को भी चिन्हित कर बंद कराया। अधिकारियों के अनुसार, इससे पहले भी इस इलाके में कार्यवाही की जा चुकी थी, लेकिन कुछ स्थानों पर दोबारा अवैध गतिविधियां शुरू हो गई थीं, जिन पर अब कड़ी निगरानी रखी जाएगी। पूरी कार्रवाई का नेतृत्व खनि निरीक्षक अभिषेक पटले ने किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अवैध खनन में लिप्त लोगों के खिलाफ आगे भी कठोर कदम उठाए जाएंगे और दोषियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे अवैध गतिविधियों से दूर रहें और ऐसी किसी भी जानकारी की तुरंत सूचना संबंधित विभाग को दें, ताकि प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

सीमांकन में '50 हजार की डील' राजस्व अमले पर रिश्वतखोरी के गंभीर आरोप

नवभारत,शहडोल। जिले के सोहागपुर तहसील क्षेत्र में जमीन सीमांकन को लेकर राजस्व विभाग एक बार फिर सवालों के घेरे में है। वार्ड क्रमांक 30, पुरानी बस्ती (शीतला मंदिर के पास) निवासी सरिता वर्मा ने कलेक्टर को लिखित शिकायत सौंपते हुए राजस्व निरीक्षक भास्कर दत्त गौतम और पटवारी विपुल सिंह पर रिश्वत मांगने और काम में लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत में बताया गया है कि सरिता वर्मा की पैतृक जमीन ग्राम गोरतरा में स्थित है, जिसका खसरा नंबर 578ध्1 और रकबा 0.340 हेक्टेयर है। उन्होंने 19 नवंबर 2025 को लोक सेवा केंद्र सोहागपुर के माध्यम से सीमांकन के लिए आवेदन किया था, लेकिन कई महीनों बाद भी जमीन का सीमांकन नहीं किया गया।

50 हजार की मांग-बताया गया है कि तहसीलदार सोहागपुर द्वारा 10 दिसंबर 2025 को आदेश जारी कर सीमांकन के लिए टीम भी गठित की गई थी, इसके बावजूद संबंधित कर्मचारियों ने सिर्फऔपचारिक सूचना देकर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। पीड़िता का आरोप है कि राजस्व निरीक्षक और पटवारी द्वारा उनके पति से 50 हजार रुपये की मांग की जा रही है, तभी सीमांकन कार्य कराने की बात कही जा रही है।सरिता वर्मा का कहना है कि इस मामले को लेकर वे पूर्व में जनसुनवाई में भी शिकायत कर चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इससे उनका परिवार मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सीमांकन जैसे जरूरी कार्यों में भी रिश्वत की मांग आम होती जा रही है, जिससे आम जनता का भरोसा व्यवस्था से उठता जा रहा है। पीड़िता ने कलेक्टर से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराकर जल्द से जल्द सीमांकन कराया जाए और दोषी अधिकारियों-कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए।

मां गंगा-सा विस्तार, सुख-समृद्धि अपार
नवनिर्माण के 9 वर्ष
गंगा एक्सप्रेसवे
मेरठ · प्रयागराज · हापुड़ · प्रतापगढ़ · बुलंदशहर · रायबरेली · अमरोहा · उन्नाव · सम्भल · बदायूं · शाहजहांपुर · हरदोई

₹36,230 करोड़
से निर्मित उत्तर प्रदेश के सबसे विराट
594 कि.मी. लम्बे गंगा एक्सप्रेसवे (मेरठ-प्रयागराज) का
लोकार्पण
प्रधानमंत्री
नरेन्द्र मोदी
के द्वारा

विस्तार भी-रफ्तार भी : 6 लेन वाले (8 लेन में विस्तारणीय) गंगा एक्सप्रेसवे से 12 जनपद आच्छादित • डिजाइन स्पीड 120 कि.मी./घंटा, मेरठ से प्रयागराज की दूरी 6 से 8 घंटे में होगी पूरी • हापुड़ में गंगा नदी पर 960 मीटर एवं बदायूं में रामगंगा नदी पर 720 मीटर का दीर्घ सेतु • मेरठ एवं प्रयागराज में 2 मुख्य टोल प्लाजा सहित कुल 21 रैम्प इंटरचेंज • पूर्णतः प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड गंगा एक्सप्रेसवे पर एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम • लड़ाकू विमानों की आपात लैंडिंग एवं टेक-ऑफ हेतु शाहजहांपुर के समीप 3.50 कि.मी. लम्बी हवाई पट्टी • एक्सप्रेसवे के दोनों ओर 3.75 मी. चौड़ी स्टैगर्ड सर्विस लेन

विकास भी-कल्याण भी : फ्यूल एवं ई-चार्जिंग सुविधा के साथ 9 विशाल जन-सुविधा परिसर • गंगा एक्सप्रेसवे के 12 जनपदों में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकास का कार्य गतिमान • औद्योगिक इकाइयों एवं कृषि उत्पादन क्षेत्रों की दिल्ली से तीव्र कनेक्टिविटी • कृषि, वाणिज्य, पर्यटन एवं औद्योगिक आय में होगी वृद्धि • दुग्ध, सब्जी, फल के भंडारण एवं प्रसंस्करण के नवीन केंद्र खुलेंगे • व्यापार एवं रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा • नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, उच्च शिक्षण एवं मेडिकल संस्थानों के लिए असीम संभावनाएं

गरिमामयी उपस्थिति
आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश | योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश
पंकज चौधरी, राज्य मंत्री, वित्त, भारत सरकार | जितिन प्रसाद, राज्य मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, वाणिज्य एवं उद्योग, भारत सरकार | केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश | ब्रजेश पाठक, उप मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश
सुरेश कुमार खन्ना, मंत्री, वित्त एवं संसदीय कार्य, उत्तर प्रदेश | नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', मंत्री, औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, एन.आर.आई. तथा निवेश प्रोत्साहन, उत्तर प्रदेश

नितिन अग्रवाल, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), आबकारी एवं मद्य निषेध, उत्तर प्रदेश | असीम अरुण, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, उत्तर प्रदेश | जयेन्द्र प्रताप सिंह राठौर, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), सहकारिता, उत्तर प्रदेश | नरेन्द्र कुमार कश्यप, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण, उत्तर प्रदेश | जसवन्त सिंह सैनी, राज्य मंत्री, संसदीय कार्य तथा औद्योगिक विकास, उत्तर प्रदेश
रजनी तिवारी, राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश | जय प्रकाश, सांसद, हरदोई | अशोक कुमार रावत, सांसद, मिश्रिख | अरुण कुमार सागर, सांसद, शाहजहांपुर | डॉ. स्वामी सच्चिदानंद हरि साक्षी महाराज, सांसद, उन्नाव | मिथलेश कुमार, सदस्य, राज्य सभा

शकुन सिंह, अध्यक्ष, जिला पंचायत, उन्नाव | ममता यादव, अध्यक्ष, जिला पंचायत, शाहजहांपुर | प्रिया शाक्य, अध्यक्ष, जिला पंचायत, कन्नौज | प्रेमावती पी.के. वर्मा, अध्यक्ष, जिला पंचायत, हरदोई | अर्चना वर्मा, महापौर, शाहजहांपुर | माधवेन्द्र प्रताप सिंह, विधायक, सवाइजपुर | श्याम प्रकाश, विधायक, गोपामऊ | प्रभाष कुमार, विधायक, संडी | आशीष कुमार सिंह 'आशू', विधायक, बिलग्राम-मल्लावां | रामपाल वर्मा, विधायक, बालामऊ | अलका सिंह 'अर्कवंशी', विधायक, संडीला | हरि प्रकाश वर्मा, विधायक, जलालाबाद
अर्चना पाण्डेय, विधायक, छिबरामऊ | पंकज गुप्ता, विधायक, उन्नाव | कैलाश राजपूत, विधायक, तिर्वा | आशुतोष शुक्ल, विधायक, भगवन्त नगर | अरविन्द कुमार सिंह, विधायक, दरौली | श्रीकान्त कटियार, विधायक, बांगरमऊ | सलोना कुशवाहा, विधायक, तिलहर | अनिल कुमार सिंह, विधायक, पुरवा | चेतराम, विधायक, पुवायां | बम्बा लाल, विधायक, सफीपुर | डॉ. वीर विक्रम सिंह 'प्रिंस', विधायक, करता | बृजेश कुमार, विधायक, मोहान
अरुण पाठक, सदस्य, विधान परिषद | डॉ. मानवेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, विधान परिषद | इंजी. अवनीश कुमार सिंह, सदस्य, विधान परिषद | डॉ. सुधीर गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद | अशोक अग्रवाल, सदस्य, विधान परिषद | उमेश द्विवेदी, सदस्य, विधान परिषद | राम चन्द्र प्रधान, सदस्य, विधान परिषद | प्रांशु दत्त द्विवेदी, सदस्य, विधान परिषद | डॉ. आकाश अग्रवाल, सदस्य, विधान परिषद
एवं अन्य गणमान्य महानुभाव

दिनांक : 29 अप्रैल, 2026 | समय : प्रातः 10:00 बजे | स्थान : मल्लावां कट, निकट चैनेज 351 कि.मी. गंगा एक्सप्रेसवे, तहसील - बिलग्राम, जनपद - हरदोई, उ.प्र.

सुपरफास्ट प्रदेश- उत्तर प्रदेश : 8 एक्सप्रेसवे संचालित, 14 विकास के विभिन्न चरणों में • देश के कुल एक्सप्रेसवे का 55% भाग उत्तर प्रदेश में मौजूद • एक्सप्रेसवे के आसपास 26 जनपदों के 27 स्थलों पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर • औद्योगिक विकास हेतु अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का क्रियान्वयन • पीएम गति शक्ति को लागू करने वाला अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश • अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत प्रयागराज एवं आगरा में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापना का कार्य गतिमान • ईस्टर्न एवं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जंक्शन दादरी (उत्तर प्रदेश) में स्थित • देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क उत्तर प्रदेश में (16,000 किलोमीटर) • 17 एयरपोर्ट संचालित (5 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट), 7 विकास के विभिन्न चरणों में • राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (वाराणसी-हल्दिया) के अयोध्या तक विस्तार का कार्य प्रगति पर

विकास की गति अपार-डबल इंजन सरकार
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश | लाइव प्रसारण DD NEWS & Youtube.com/DDNEWS
UPGovtOfficial | CMOUttarpradesh | CMOfficeUP